जनरल इंस्ट्रूमेंट्स कंपनी

वी. यूनियन ऑफ इंडिया एवं ओआरएस।

(सिविल अपील संख्या **5222/2008)**

25 अगस्त **2008**

[सी.के. ठक्कर और डी.के. जैन**,** जे.जे.जे**]**

निर्यात-आयात नकद प्रतिपूर्ति सहायता (सीसीएस) - सरकारी उपक्रम द्वारा जारी वैश्विक निविदा का दावा आपूर्तिकर्ता फर्म द्वारा कच्चे माल का आयात - शुल्क की रियायती दर पर आयात लाइसेंस के लिए आवेदन हालांकि, बांड के निष्पादन के अधीन विशेष अग्रदाय लाइसेंस (एसआईएल) जारी करना - इसके बाद, ई को पूरा करने के लिए फर्म के खिलाफ जब्ती आदेश अधिकारी एसआईएल को आयात के लिए लाइसेंस में बदल देंगे, लेकिन सीसीएस के दावे को खारिज कर दिया - अपील पर, आयोजित: सुनवाई के दौरान, अधिकारियों ने सीसीएस के लिए पर्याप्त दावे की अनुमति दी, हालांकि, दस्तावेजी साक्ष्य के अभाव में शेष दावे को खारिज कर दिया। चूंकि एसआईएल को परियोजना आयात लाइसेंस में परिवर्तित कर दिया गया था, शेष सीसीएस के लिए एफ का दावा नहीं दिया जा सकता है - हालांकि, चूंकि 9% प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ। आक्षेपित निर्णय की तिथि से वास्तविक भुगतान की तिथि तक।

भारत सरकार के उपक्रम आरसीएफ ने अपनी परियोजना के लिए पूंजीगत वस्तुओं की आपूर्ति के लिए एक वैश्विक निविदा जारी की। अपीलकर्ता-साझेदारी फर्म ने केबलों की आपूर्ति के लिए अपना कोटेशन प्रस्तुत किया। आरसीएफ ने निविदा स्वीकार कर ली और रुपये की केबल खरीदने पर सहमति व्यक्त की। खरीद आदेश द्वारा अपीलकर्ता से 17,49,000/- रु. अपीलकर्ता ने कच्चे माल के आयात के लिए शुल्क छूट पात्रता प्रमाण पत्र आदि के साथ आयात लाइसेंस के लिए आयात और निर्यात के संयुक्त मुख्य नियंत्रक को आवेदन किया। इसके बाद, अपीलकर्ता ने आरसीएफ से अनिवार्यता प्रमाणपत्र प्राप्त किया और इसे जेसीसीआई को भेज दिया। हालाँकि परियोजना को पूरी तरह से भारत सरकार द्वारा वित्तपोषित किया गया था, जेसीसीआई ने एएम 84 नीति के तहत अपीलकर्ता को एक विशेष अग्रदाय लाइसेंस (एसआईएल) जारी किया, जिससे अपीलकर्ता को सूचीबद्ध कच्चे माल को 5,78,300/- रुपये में आयात करने की अनुमति मिल गई। सीमा शुल्क के भुगतान के बिना, कुछ शर्तों के अधीन। इसके अनुसरण में, बांड निष्पादित किया गया। अपीलकर्ता ने कच्चे माल का आयात किया और परिणामी उत्पादों के निर्माण में उनका उपयोग किया, जिसका मूल्य 17,59,382/- रुपये था; 17,49,000/- रुपये के निर्यात दायित्व के विरुद्ध आरसीएफ को आपूर्ति की गई। इसके बाद, अपीलकर्ता ने शुल्क छूट पात्रता प्रमाणपत्र पर अपेक्षित समर्थन के लिए आरसीएफ से संपर्क किया। आरसीएफ ने डीईईसी बुक पर

अपेक्षित समर्थन किया कि अपीलकर्ता ने 27.07.1983 से 10.05.1984 तक 17,59,382/- रुपये मूल्य के सामान की आपूर्ति की थी। इस बीच, जेसीसीआई ने अपीलकर्ता को कारण बताओ नोटिस जारी किया और उन्हें उनके द्वारा प्रस्तुत 12,14,623/- रुपये के बांड को लागू करने के लिए कहा क्योंकि उन्होंने लाइसेंस और बांड का उल्लंघन किया था। आयात और निर्यात नियंत्रक ने माना कि अपीलकर्ता निर्यात दायित्व को पूरा करने और निर्धारित दस्तावेजों को समय पर प्रस्तुत करने में विफल रहा। इसने अपीलकर्ता को 12,14,623/- रुपये की बांड राशि जमा करने का निर्देश दिया; वैध आर.ई.पी. को सरेंडर करने के लिए लाइसेंस अप्रयुक्त रहने पर 18% प्रति वर्ष की दर से ब्याज सहित सीमा शुल्क का भुगतान करना होगा। ज़ब्ती आदेश के परिणामस्वरूप, आयात और निर्यात नियंत्रक ने अपीलकर्ता को नकद सहायता देने से इनकार कर दिया।

अपीलकर्ता ने ज़ब्ती आदेश के विरुद्ध अपील दायर की। जिसे अस्वीकार कर दिया गया. इसके बाद अपीलकर्ता ने दूसरी अपील दायर की। लंबितता के दौरान, सीमा शुल्क अधिकारियों ने एसआईएल के तहत शुल्क के भुगतान के बिना आयातित और निकासी किए गए कच्चे माल के संबंध में अपीलकर्ता से 3,71,614.82 रुपये की सीमा शुल्क की वसूली की मांग की। अपीलकर्ता ने रिट याचिका दायर की जिसका निपटारा कर दिया गया क्योंकि अपीलकर्ता ने स्वेच्छा से सीमा शुल्क शुल्क जमा करने की पेशकश

की थी। आदेशित इसके बाद दिनांक 21.02.03 के आदेश से द्वितीय अपील भी खारिज कर दी गई। लाइसेंसिंग प्राधिकारी ने अपीलकर्ता के खिलाफ विभागीय कार्यवाही शुरू की। उसके विरुद्ध अपील खारिज कर दी गई। हालाँकि, रोक की अवधि को 31.03.1989 तक कम करके दूसरी अपील को आंशिक रूप से अनुमति दी गई थी। इसके बाद अपीलकर्ता ने आदेश के खिलाफ रिट याचिका दायर की

दिनांक 23.02.03. इसके लंबित रहने के दौरान, अपीलकर्ता ने मंत्रालय को अभ्यावेदन दिया, जिसमें एसआईएल के डी को परियोजना आयात लाइसेंस में परिवर्तित करने की मांग की गई। हालाँकि, प्रतिनिधित्व अस्वीकार कर दिया गया था। अपील में, उच्च न्यायालय ने माना कि अपीलकर्ता के विरुद्ध ज़ब्ती आदेश अनावश्यक था; वह भले ही द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी ने ऐसा माना हो ज़ब्ती के कारण कोई वित्तीय निहितार्थ नहीं है-पूर्व आदेश, फिर भी उसके आधार पर, अपीलकर्ता बनाया गया था ब्याज और कलम सहित संपूर्ण सीमा शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी- अल्टी; एक बार यह स्वीकार कर लिया जाए कि इसे जारी करना एक गलती थी अपीलकर्ता को एसआईएल और उससे जुड़ी शर्तें बांड और लाइसेंस का पालन करना पूरी तरह से असंभव था, लाइसेंसिंग प्राधिकारियों को उपाय करना चाहिए था कदम। हाईकोर्ट ने निर्देश देते हुए रिट याचिका का निस्तारण कर दिया अपीलकर्ता द्वारा निष्पादित बांड/बैंक गारंटी लागू

नहीं किया जाएगा और जेसीसीआई एसआईएल में संशोधन करेगा आयात के लिए लाइसेंस में। हालांकि, हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया नकद प्रतिपूरक सहायता के लिए प्रार्थना। इसलिए वर्तमान अपील

न्यायालय ने अपील को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए

अभिनिर्धारित 1. किसी भी व्यक्ति को अनियमितताओं की तकनीकी कैल प्रक्रिया द्वारा गलत नहीं सहना चाहिए। नियम या प्रक्रियाएँ जनरल इंस्ट्रूमेंट्स कंपनी बनाम यूनियन न्याय की दासी हैं, न्याय की स्वामिनी नहीं। एक्स डेबिटो जस्टिटिया, उसके साथ न्याय होना चाहिए।' [पैरा 22] [559-एफ]

ए.आर. अंतुले बनाम. आर.एस. नायक 1988 (2) एससीसी 602-भरोसेमंद पर।

2.1 वर्तमान मामले में, हालांकि अपीलकर्ता को जारी किए जाने वाले लाइसेंस की प्रकृति में भ्रम के कारण नुकसान उठाना पड़ा है, लेकिन विशेष अग्रदाय लाइसेंस को एक परियोजना आयात लाइसेंस में परिवर्तित करने के लिए अपीलकर्ता की मुख्य प्रार्थना को मंजूरी दे दी गई है। उच्च न्यायालय, गलती का काफी हद तक निवारण हो गया है। [पैरा 22] [559-जी]

2.2 सुनवाई के दौरान, विदेश व्यापार के जोनल संयुक्त महानिदेशक के कार्यालय ने उच्च न्यायालय की टिप्पणियों के मद्देनजर 14.03.2008

को अपीलकर्ता द्वारा दिए गए प्रतिनिधित्व की जांच की। आदेश दिनांक 8.04.2008 द्वारा, विदेश व्यापार विकास अधिकारी ने अपीलकर्ता को सूचित किया कि 5,52,032.92 रुपये के सीसीएस दावे में से, उन्हें 4,19,916/- रुपये के दावे के लिए पात्र पाया गया है, और विभाग उक्त राशि देने को तैयार था। हालाँकि, शेष सीसीएस दावा और उस पर ब्याज अस्वीकार कर दिया गया था। संचार से यह स्पष्ट है कि सीसीएस के लिए एक बड़ा दावा स्वीकार किया गया है और रु. 1,31,953/- का शेष दावा दस्तावेजी साक्ष्य के अभाव में अस्वीकार कर दिया गया है, जिससे पता चलता है कि परियोजना को द्विपक्षीय या बहुपक्षीय विदेश द्वारा वित्त पोषित किया गया था। - सामान्य सहायता. यह नोट करना उचित है कि उक्त पत्र में इस बात का कोई संकेत नहीं है कि पहली बार में अपीलकर्ता को 4,19,916/- रुपये का सीसीएस दावा क्यों अस्वीकार कर दिया गया था। [पैरा 18 और 19] [556-जी-एच, 557-ए, 558-डी-ई]

2.3 उच्च न्यायालय के निर्देश के अनुसार एसआईएल को परियोजना आयात लाइसेंस में बदलने के बाद की हस्तक्षेपकारी घटनाओं के आलोक में मामले पर विचार करने के बाद, सीसीएस दावे के संबंध में अपीलकर्ता को कोई और राहत नहीं दी जा सकती है। मामले को ध्यान में रखते हुए, प्रमाणपत्र-आरसीएफ द्वारा अपीलकर्ता को जारी की गई और दिनांक 03.06.2008 की लिखित दलीलों के साथ संलग्न की गई अपील का

अपीलकर्ता को कोई फायदा नहीं हुआ। फिर भी, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि दूसरे अपीलीय प्राधिकारी ने ज़ब्ती आदेश के बी खाते पर दिनांक 04.05.1987 को पारित आदेश के अनुसार रोक की अवधि को केवल 31.03.1989 तक कम कर दिया था और यह तथ्य कि उच्च न्यायालय ने इसके द्वारा दिनांक 07.04.2006 के आदेश में माना गया कि अपीलकर्ता के खिलाफ ज़ब्ती आदेश अनावश्यक था, कम से कम उच्च न्यायालय द्वारा आदेश पारित होने पर सीसीएस राशि जारी नहीं करने के लिए विदेश व्यापार महानिदेशक के पास कोई उचित कारण नहीं था। इस अपील की सुनवाई के दौरान ही उक्त उत्तरदाताओं के वकील ने दावे की दोबारा जांच कराने की पेशकश की और अब दिनांक 08.04.2008 के आदेश के अनुसार, अपीलकर्ता का दावा 4,19,916 रुपये की सीमा तक है। /- व्यवस्थित पाया गया है। परिसर में, यह स्पष्ट है कि उत्तरदाताओं ने अपीलकर्ता को देय राशि को कानून के अधिकार के बिना सीसीएस के रूप में बरकरार रखा है और वे तुरंत इसका भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हैं। इस प्रकार, उत्तरदाताओं को सीसीएस दावा जारी करने का निर्देश दिया जाता है, जो अपील-सी डी के कारण निर्धारित किया गया है आज से चार सप्ताह के भीतर ब्याज सहित जमा करें 07.04.2006 से वास्तविक तारीख तक 9% प्रति वर्ष की दर भुगतान। [पैरा 23-24] [560-ए-एफ]

केस कानून संदर्भ

1988 (2) एससीसी **602** पर भरोसा। पैरा **22**

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 5222/2008

2003 की रिट याचिका संख्या 1174 जी में बॉम्बे उच्च न्यायालय के अंतिम निर्णय और आदेश दिनांक 7.04.2006 से

एम.एम. कुलकर्णी व्यक्तिगत रूप से अपीलकर्ता।

वी. शेखर, संजीव के. भारद्वाज। प्रतिवादियों की ओर से किरण भारद्वाज, बी. कृष्णा प्रसाद, गौरव अग्रवाल, अनिल कटियार और डी.एस. महरा एच.

कोर्ट का फैसला डी.के. द्वारा सुनाया गया।

[डी**.**के**.** जैन**,** जे**.]**.: 1. स्वीकृति प्रदान की गयी।

2. यह अपील, विशेष अनुमति द्वारा, रिट याचिका संख्या 1174 / 2003 में बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और आदेश दिनांकित 07.04.2006 से उत्पन्न हुई है।

3. इन कार्यवाहियों से जुड़े भौतिक तथ्य इस प्रकार निम्न: हैं-

वर्ष 1982 में, भारत सरकार के उपक्रम मेसर्स राष्ट्रीय केमिकल्स एंड

फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (बाद में 'आरसीएफ' के रूप में संदर्भित) ने अपनी थाल परियोजना के लिए आवश्यक विभिन्न प्रकार के पूंजीगत सामानों की आपूर्ति के लिए एक वैश्विक निविदा जारी की। उक्त निविदा नोटिस का जवाब देते हुए, अपीलकर्ता, एक साझेदारी फर्म, ने अपने प्रबंध भागीदार, श्री मनोहर एम. कुलकर्णी, एक पूर्व-सैनिक, के माध्यम से थर्मोकपल क्षतिपूर्ति केबल और एक्सटेंशन केबल की आपूर्ति के लिए अपना कोटेशन प्रस्तुत किया। आरसीएफ द्वारा निविदा स्वीकार कर ली गई और 13 अक्टूबर, 1982 के एक खरीद आदेश द्वारा, वे अपीलकर्ता से 17,49,000/- रु. के केबल खरीदने पर सहमत हुए।

4. आरसीएफ को आपूर्ति की जाने वाली पूंजीगत वस्तुओं के निर्माण में आवश्यक कुछ कच्चे माल के आयात पर सीमा शुल्क छूट का लाभ उठाने के लिए, 22 नवंबर, 1982 को अपीलकर्ता ने आयात और निर्यात के संयुक्त मुख्य नियंत्रक संक्षिप्त में जेसीसीआई), बॉम्बे के पास एएम 83 के लिए आयात नीति बुक के संदर्भ में शुल्क मुक्त या शुल्क की रियायती दर पर कच्चे माल के आयात के लिए शुल्क छूट पात्रता प्रमाण पत्र आदि के साथ एक आयात लाइसेंस जारी करने के लिए आवेदन किया। अपीलकर्ता को, क्योंकि वे उस फॉर्म के बारे में स्पष्ट नहीं थे जिस पर उन्हें आवेदन करना था, आवेदन के साथ दायर किए गए कवरिंग पत्र पर, अग्रिम लाइसेंसिंग समिति के साथ-साथ विशेष अग्रदाय लाइसेंसिंग समिति को

प्रतियों के साथ नई दिल्ली में, उक्त आवेदनों को संबंधित सेल को अग्रेषित करने का अनुरोध किया गया था ताकि उपरोक्त उद्देश्य के लिए एक उचित लाइसेंस जारी किया जा सके।

5. आवेदन के प्रसंस्करण पर, जेसीसीआई बम्बई के कार्यालय ने अपने दिनांक 30 नवम्बर 1982 के पत्र द्वारा बुलाया अपीलकर्ता को आरसीएफ से अनिवार्यता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है। तदनुसार, अपीलकर्ता ने परियोजना प्राधिकरण यानी आरसीएफ से अनिवार्यता प्रमाण पत्र प्राप्त किया, इस आशय का कि वे 17,49,000/- रु.का सामान खरीदने के लिए सहमत हुए हैं। वैश्विक निविदा प्रक्रिया के तहत उनकी थाल परियोजना के लिए अपीलकर्ता से और यह कि थाल परियोजना पूरी तरह से भारत सरकार द्वारा वित्तपोषित है। आरसीएफ द्वारा जारी प्रमाण पत्र में, यह भी कहा गया था कि अपीलकर्ता आयात नीति 1981-82 के पैरा 14 के अनुसार केबलों की संरचना के विनिर्माण के लिए उनके द्वारा आयातित कच्चे माल पर आयात शुल्क की रियायती दर का लाभ उठाने के लिए पात्र था। अपीलकर्ता ने उक्त प्रमाणपत्र जेसीसीआई, बॉम्बे को भेज दिया। इस स्पष्ट ज्ञान के बावजूद कि आरसीएफ की थाल परियोजना पूरी तरह से भारत सरकार द्वारा वित्तपोषित थी, आयात और निर्यात नियंत्रक, बॉम्बे ने एएम 84 नीति के तहत 30 मई, 1983 को अपीलकर्ता को सीमा शुल्क के भुगतान के बिना

अनुमानित मूल्य रु. 5,78,300/- के लिए सूचीबद्ध कच्चे माल का आयात करने की अनुमति देना प्रदान करते हुए एक विशेष अग्रदाय लाइसेंस जारी किये हालाँकि, लाइसेंस निम्नलिखित शर्तों के अधीन था:

> "(ए) अपीलकर्ता उक्त लाइसेंस के खिलाफ पहली खेप की निकासी की तारीख से 6 महीने के भीतर आरसीएफ को 17,49,000/- रुपये के एफओबी मूल्य पर संलग्न सूची के अनुसार निर्यात वस्तुओं की आपूर्ति करेगा।
>
> (बी) उक्त लाइसेंस के तहत निर्यात दायित्व की पूर्ति सुनिश्चित करने के लिए, अपीलकर्ता को आयात निर्यात प्रक्रिया 1981-82 की हैंडबुक के परिशिष्ट-38 में दिए गए प्रोफार्मा के अनुसार 100% बैंक गारंटी के साथ 12,14,623 रुपये की राशि के लिए एक बांड निष्पादित करना होगा।
>
> (सी) उक्त अग्रिम लाइसेंस के विरुद्ध आयातित माल का उपयोग समय-समय पर संशोधित सीमा शुल्क अधिसूचना संख्या 11/एफ- संख्या 602/14/8/डीबीके दिनांक 09.06.78 के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा।
>
> (डी) नकद सहायता, यदि कोई हो, वाणिज्य मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुसार होगी।

(ई) निर्धारित समय के भीतर, निर्यात दायित्व को पूरा करने में विफलता की स्थिति में बांड लागू किया जाएगा और लाइसेंस धारक निर्यात नहीं किए गए उत्पादों के अनुरूप सामग्री की आनुपातिक मात्रा पर सीमा शुल्क का भुगतान करेगा।

6. उपर्युक्त शर्त (बी) के अनुसार अपेक्षित बांड तदनुसार 17 जून, 1983 को निष्पादित किया गया था। अपीलकर्ता ने समय-समय पर कुल सीआईएफ को मूल्य 3,01,439/- रुपये के कच्चे माल का आयात किया और बांड के संदर्भ में शुल्क के भुगतान के बिना इसे चुका दिया गया । यह विवाद में नहीं है कि अपीलकर्ता ने परिणामी उत्पादों के निर्माण में आयातित कच्चे माल की पूरी मात्रा का उपयोग किया है, जिसका मूल्य C रुपये 17,59,382/- है; निर्यात दायित्व को पूरा करने के लिए आरसीएफ को आपूर्ति की गई, जैसा कि लाइसेंस में निर्धारित है, रु. 17,49,000/- के निर्यात दायित्व के विरुद्ध।

7. इस प्रकार, निर्यात दायित्व को पूरा करने के बाद, अपीलकर्ता ने परियोजना प्राधिकरण के लिए संपर्क किया, अर्थात आरसीएफ से शुल्क छूट पात्रता प्रमाणपत्र (संक्षेप में 'डीईईसी') पर अपेक्षित समर्थन के लिए। शुरुआत में आरसीएफ ने इस आधार पर समर्थन देने से इनकार कर दिया कि थाल परियोजना को भारत सरकार द्वारा वित्तपोषित किया गया था, न

कि विश्व बैंक, ओईसीएफ, एडीबी आदि जैसे संगठनों द्वारा, जैसा कि छूट अधिसूचना संख्या 210/82 दिनांकित 10 मई 1984 के तहत विचार किया गया था। हालाँकि, बाद में, आरसीएफ ने 2 फरवरी, 1988 को डीईईसी पुस्तक पर अपेक्षित समर्थन किया कि अपीलकर्ता ने 27 जुलाई 1983 से इस अवधि के दौरान 17,59,382/- रुपये मूल्य के सामान की आपूर्ति की थी।

8. ऐसा प्रतीत होता है कि इस बीच, जेसीसीआई, बॉम्बे द्वारा 5/6 सितंबर, 1985 को एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, जिसमें अपीलकर्ता को यह बताने के लिए कहा गया था कि क्यों। उनके द्वारा प्रस्तुत 12,14,623/- रूपये की राशि के बाॅंड को लागू नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि अपीलकर्ता ने लाइसेंस के खंड 1 और बांड के खंड 5 का उल्लंघन किया है। अपीलकर्ता को श्री जी.आर. के समक्ष उपस्थित होना आवश्यक था। नायर, आयात और निर्यात के उप मुख्य नियंत्रक, 20 सितंबर, 1985, अपराह्न 3:15 बजे। व्यक्तिगत सुनवाई के लिए, जो वास्तव में 29 सितंबर को दी गई थी-बेर, 1985। दिखाए गए कारण से संतुष्ट नहीं होकर श्रीमती आर. जॉनी द्वारा 4 दिसंबर, 1985 को एक साइक्लोस्टाइल आदेश पारित किया गया था। आयात और निर्यात नियंत्रक आर. जॉनी ने कहा कि अपीलकर्ता समय पर निर्यात दायित्व को पूरा करने में विफल रहा और निर्धारित बी अवधि के भीतर निर्धारित दस्तावेज

प्रस्तुत करने में विफल रहा, और इस प्रकार, बांड की शर्त संख्या 5 का उल्लंघन किया। तदनुसार, अपीलकर्ता को 12,14,623/- रुपये की बांड राशि जमा करने का निर्देश दिया गया; वैध आर.ई.पी. को सरेंडर करने के लिए लाइसेंस अप्रयुक्त रहने पर और छूट प्राप्त सामग्री की आनुपातिक मात्रा पर 18% की दर से ब्याज के साथ सीमा शुल्क का तुरंत भुगतान करने के निर्देश दिए गए। दूसरे शब्दों में, अपीलकर्ता द्वारा आरसीएफ को की गई आपूर्ति को लाइसेंस की शर्त (ए) के संदर्भ में निर्यात दायित्व के निर्वहन के रूप में नहीं माना गया था। अपीलकर्ता को डिफॉल्टर घोषित कर दिया गया, जिससे उसे शुल्क छूट योजना के तहत या समय-समय पर घोषित आयात निर्यात नीति के किसी भी अन्य प्रावधान के तहत कोई भी लाइसेंस प्राप्त करने से रोक दिया गया।

9. 4 दिसंबर, 1985 के ज़ब्ती आदेश के परिणामस्वरूप, आयात और निर्यात नियंत्रक ने 20 दिसंबर, 1985 के पत्र के माध्यम से अपीलकर्ता को नकद सहायता देने से इनकार कर दिया। 4 दिसंबर, 1985 के ज़ब्ती आदेश के विरुद्ध अपीलकर्ता द्वारा की गई अपील को श्रीमती आर. जॉनी द्वारा जारी आदेश दिनांक 21 मई, 1986 द्वारा निम्न आधार पर खारिज कर दी गई थी। आयात और निर्यात नियंत्रक ने (i) परियोजना प्राधिकरण द्वारा विधिवत प्रमाणित डीईईसी पुस्तक का भाग 'एफ' प्रस्तुत नहीं किया गया था और (ii) मूल रूप में निर्यात का प्रमाण पत्र और न ही

मूल निर्यात एफ दस्तावेज अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत किए गए थे। अपीलकर्ता संयोगवश, ज़ब्ती आदेश और अपीलीय आदेश एक ही अधिकारी अर्थात् श्रीमती आर. जॉनी द्वारा पारित किया गया था। हालांकि अपीलीय आदेश जेसीसीआई की मंजूरी के साथ जारी किया चाहिए था।

10. इससे व्यथित होकर, अपीलकर्ता ने संयुक्त महानिदेशक, विदेश व्यापार, नई दिल्ली की एक समिति के समक्ष दूसरी जी अपील दायर की।

11. दूसरी अपील के लंबित रहने के दौरान, सीमा शुल्क अधिकारियों ने विशेष अग्रदाय लाइसेंस (एसआईएल) दिनांकित 30 मई, 1983 के के तहत शुल्क के भुगतान के बिना आयात और निकासी की गई। सीमा शुल्क की राशि वसूलने की मांग क कच्चे माल जनरल इंस्ट्रूमेंट्स कंपनी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया और ओआरएस के संबंध में अपीलकर्ता से रु. 3,71,614.82 को प्रस्तावित कार्रवाई को अपीलकर्ता द्वारा की रिट याचिका संख्या 2038/ 1988 को प्राथमिकता देकर चुनौती दी गई थी। हालांकि, जब याचिका को अंतिम सुनवाई के लिए लिया गया था 21 अक्टूबर, 2002 को अपीलकर्ता के वकील ने स्वेच्छा से मांग के अनुसार सीमा शुल्क जमा करने की पेशकश की। इसके बाद, राजस्व के वकील ने एक बयान दिया कि उक्त राशि जमा होने के दो सप्ताह के भीतर, एक उचित कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा और उस पर कानून के अनुसार फैसला सुनाया जाएगा। इस प्रकार, रिट याचिका का उसी दिन निपटारा कर दिया

गया। हालाँकि, रिट याचिका का निपटारा करते समय, यह आदेश दिया गया था कि 21 मई, 1986 के आदेश के खिलाफ अपीलकर्ता द्वारा दायर अपील का निपटारा छह महीने की अवधि के भीतर किया जाएगा।

12. अपीलीय समिति, जिसमें विदेश व्यापार, नई दिल्ली के दो संयुक्त महानिदेशक शामिल हैं, ने यह देखते हुए कि अपीलकर्ता द्वारा दायर की गई दूसरी अपील निर्यात-आयात नीति की प्रक्रिया की वर्तमान हैंडबुक के अनुसार मुख्य-योग्य नहीं थी। जब्ती आदेश के खिलाफ दूसरी अपील का कोई प्रावधान नहीं था, उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों के सम्मान में अपील की सुनवाई गुण-दोष के आधार पर की गई। दिनांक 21 फरवरी, 2003 के आदेश के अनुसार, समिति ने माना कि हालाँकि ज़ब्ती आदेश और पहली अपील में पारित आदेश नीति के अनुरूप थे, फिर भी इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि ज़ब्ती आदेश वास्तव में बैंक में लागू नहीं किया गया था। स्तर पर और व्यवहारिक रूप से कोई राशि अपीलकर्ता के खाते से सरकार के खाते में स्थानांतरित नहीं की गई थी, जब्ती आदेश का अपीलकर्ता पर कोई वित्तीय प्रभाव नहीं पड़ा और इसलिए दूसरी अपील में कोई राहत देने की आवश्यकता नहीं थी। तदनुसार, दूसरी अपील भी खारिज कर दी गई।

13. इस समय, यह भी ध्यान दिया जा सकता है कि 4 दिसंबर, 1985 के ज़ब्ती आदेश के माध्यम से, लाइसेंसिंग प्राधिकारी ने

अपीलकर्ता के खिलाफ विभागीय कार्यवाही शुरू की थी और 4 मई, 1987 के एक आदेश के तहत, उप मुख्य नियंत्रक आयात और निर्यात, बॉम्बे ने अपीलकर्ता और उसके साझेदारों को किसी भी आयात लाइसेंस, सीमा शुल्क निकासी परमिट, आयातित माल के आवंटन को प्राप्त करने से रोक दिया। कोई भी कैनालाइजिंग एजेंसी, और एएम 88 से एएम 90 तक किसी भी सामान को आयात करने से। विभागीय आदेश के खिलाफ अपीलकर्ता द्वारा की गई पहली अपील 28 जुलाई, 1987 को आयात और निर्यात के संयुक्त मुख्य नियंत्रक द्वारा खारिज कर दी गई थी। हालांकि, अपीलकर्ता द्वारा दायर की गई दूसरी अपील को 18 जून, 1992 को आयात और निर्यात के अतिरिक्त मुख्य नियंत्रक द्वारा 31 मार्च, 1989 तक प्रतिबंध की अवधि को कम करके आंशिक रूप से अनुमति दी गई थी। अपील को आंशिक रूप से अनुमति देते समय, अपीलीय प्राधिकारी ने, अन्य बातों के अलावा, यह देखा आयातित वस्तुओं का कोई दुरुपयोग नहीं हुआ था और अपीलकर्ता ने किसी भी समय कोई जानकारी नहीं छिपाई थी लेकिन वे ऑर्डर को निष्पादित करने के लिए आयात लाइसेंस की सही योजना की पहचान करने और चुनने में सक्षम नहीं थे। अपीलीय प्राधिकारी ने अंततः इस प्रकार निष्कर्ष निकाला:

> "अपीलकर्ताओं ने लागू नीति को गलत तरीके से समझा होगा। लेकिन, जब संदर्भ के तहत विशेष अग्रदाय लाइसेंस

उन्हें 100% शुल्क मुक्त आयात के संदर्भ में विशिष्ट निर्यात दायित्व के साथ डीम्ड निर्यात श्रेणी के तहत दिया गया था, तो उन्होंने कोई आपत्ति नहीं जताई। चूंकि वे लाइसेंस की शर्तों को स्वीकार कर लिया और लाइसेंस की शर्तों का पालन करने के लिए एक बांड भी निष्पादित किया जिसमें निर्यात दायित्व शामिल था, आयातित वस्तुओं का उपयोग किए जाने के बावजूद निर्यात दायित्व का निर्वहन करने के अपने तर्क के समर्थन में औपचारिकताओं को पूरा करना परियोजना के निष्पादन के लिए उनके लिए अनिवार्य था। आरसीएफ, थाल परियोजना के निष्पादन के लिए उन्होंने जो परियोजना निष्पादित या आपूर्ति की थी, वह डीम्ड निर्यात की श्रेणी में आने वाली परियोजना नहीं थी। यह परियोजना आईडीए/आईबीआरडी द्वारा सहायता प्राप्त नहीं थी। रूपांतरण के लिए उनका अनुरोध निर्यात की मानी गई श्रेणी में आरसीएफ, थाल परियोजना को उनकी आपूर्ति पर आयात व्यापार नियंत्रण संगठन में सक्षम प्राधिकारी द्वारा विधिवत विचार किया गया था। पत्र दिनांक 30.10.1985 के तहत, उनके अनुरोध पर विचार नहीं किया गया क्योंकि उनके द्वारा आरसीएफ, थाल परियोजना को की गई आपूर्ति डीम्ड निर्यात की श्रेणी में शामिल नहीं थी।

उन्हें भुगतान करके विशेष आयात लाइसेंस को परियोजना आयात लाइसेंस में परिवर्तित करने की सलाह दी गई थी वित्त मंत्रालय की सहमति से सीमा शुल्क और उस पर दंडात्मक ब्याज। लेकिन उन्होंने इस तथ्य पर विचार करते हुए ऐसा नहीं किया कि अपीलकर्ताओं ने लागू नीति के प्रावधानों को गलत समझा और उनकी ओर से कोई दुर्भावना नहीं थी, मैं एक उदार दृष्टिकोण अपनाने के लिए इच्छुक हूं।"

14. 22 फरवरी, 2003 के आदेश से असंतुष्ट होकर, अपीलकर्ता ने बॉम्बे हाई कोर्ट में एक नई रिट याचिका दायर की। रिट याचिका के लंबित रहने के दौरान, अपीलकर्ता ने 30 मई, 1983 के विशेष अग्रदाय लाइसेंस (एसआईएल) को एक परियोजना आयात लाइसेंस में परिवर्तित करने की मांग करते हुए, संबंधित मंत्रालय को एक नया अभ्यावेदन देने के लिए न्यायालय से अनुमति मांगी। हालाँकि, उक्त अभ्यावेदन को 22 अगस्त, 2003 को इस आधार पर खारिज कर दिया गया था कि "परियोजना आयात लाइसेंस" जैसा कुछ नहीं था और चूंकि आयात वर्ष 1983 में किया गया था जब परियोजना आयात विनियम 1965 लागू थे, बीस वर्षों के बाद स्थितियों को सत्यापित करने के लिए यह संभव नहीं था

15. अपील के तहत फैसले में, विस्तृत चर्चा के बाद और विशेष रूप

से 18 जून, 1992 के अपने आदेश में दूसरे अपीलीय प्राधिकारी की उपरोक्त टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए, उच्च न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि: (i) अपीलकर्ता के खिलाफ ज़ब्ती आदेश अनावश्यक था; (ii) भले ही दूसरे अपीलीय प्राधिकारी ने माना है कि ज़ब्ती आदेश के कारण कोई वित्तीय निहितार्थ नहीं है, फिर भी उक्त आदेश के कारण, अपीलकर्ता को ब्याज और दंड के साथ संपूर्ण सीमा शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी बनाया गया था; (iii) बॉन्ड शर्तों के साथ लाइसेंस जारी करने में लाइसेंसिंग अधिकारियों की ओर से चूक, जिसे पूरा करना असंभव था, अपीलकर्ता पर गंभीर वित्तीय प्रभाव पड़ा; (iv) एक बार जब यह स्वीकार कर लिया जाता है कि अपीलकर्ता को विशेष अग्रदाय लाइसेंस जारी करना एक गलती थी और बांड और लाइसेंस से जुड़ी शर्तों को पूरा करना पूरी तरह से असंभव था, तो लाइसेंसिंग अधिकारियों को तुरंत उपचारात्मक कदम उठाने चाहिए थे , विशेष रूप से जब विदेश व्यापार (विनियमन) नियम, 1963 के नियम 8, जेसीसीआई को लाइसेंस में संशोधन करके त्रुटि को सुधारने का अधिकार देता है। अंततः, उच्च न्यायालय ने रिट याचिका का निपटारा इस निर्देश के साथ किया कि: 21 फरवरी के आदेश के आलोक में 2003, 17 जून 1983 को अपीलकर्ता द्वारा निष्पादित बॉन/बैंक गारंटी लागू नहीं की जाएगी; और अपने आदेश की तारीख से छह सप्ताह के भीतर, जेसीसीआई, बॉम्बे विशेष अग्रदाय लाइसेंस (एसआईएल) को एक लाइसेंस में संशोधित करेगा जो अपीलकर्ता को उक्त लाइसेंस के

तहत पहले से किए गए आयात के नियमितीकरण की मांग करने का अधिकार दे सकता है। शुल्क की रियायती दर, यदि सीमा शुल्क अधिनियम के तहत अनुमति हो। हालाँकि, उच्च न्यायालय ने विशेष अग्रदाय लाइसेंस (एसआईएल) के तहत अनुमत नकद क्षतिपूर्ति सहायता, जिसे इसके बाद सीसीएस कहा जाएगा, के लिए अपीलकर्ता की प्रार्थना को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। यह आदेश का वह भाग है जिसे वर्तमान अपील में दर्शाया गया है।

16. अपीलकर्ता-फर्म के एक भागीदार श्री एम. कुलकर्णी ने इस आधार पर अपीलकर्ता की ओर से मामले पर बहस करने की अनुमति मांगी कि गलत लाइसेंस के कारण दो दशकों से अधिक समय तक मुकदमेबाजी हुई। लाइसेंसिंग अधिकारियों द्वारा जारी किए गए, फर्म बंद हो गई थी और इसलिए, उसके पास वकील की सेवाएं लेने की वित्तीय क्षमता नहीं थी। हमने अनुमति दे दी और कुछ देर तक उनकी बात सुनी।

17. इस बिंदु पर, यह नोट करना प्रासंगिक होगा कि 23 जनवरी, 2008 को सुनवाई के दौरान, विदेश व्यापार महानिदेशक की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील ने निष्पक्ष रूप से कहा कि उपरोक्त टिप्पणियों के मद्देनजर उच्च न्यायालय, वह संबंधित विभाग के अधिकारियों के साथ मामले पर चर्चा करेंगे और संभवतः अपीलकर्ता को कुछ राहत मिल सकती है, विशेष रूप से 13 स्वतंत्र आदेशों/अायात

लाइसेंस से संबंधित मामलों में, जो लाइसेंसिंग प्राधिकारी द्वारा जब्त/जब्त कर लिए गए थे। 4 दिसंबर, 1985 के ज़ब्ती आदेश के आधार पर, मामले में आगे की सुनवाई स्थगित कर दी गई।

18. उक्त प्रस्ताव के अनुसरण में और उसे आगे बढ़ाते हुए, विदेश व्यापार के जोनल संयुक्त महानिदेशक के कार्यालय ने 14 मार्च, 2008 को अपीलकर्ता द्वारा दिए गए अभ्यावेदन की जांच की। प्रतिनिधि को एक व्यक्तिगत सुनवाई की भी अनुमति दी गई थी। 8 अप्रैल, 2008 के आदेश के तहत, विदेश व्यापार विकास अधिकारी ने अपीलकर्ता को सूचित किया कि 5,52,032.92 रुपये सीसीएस दावे में से, उन्हें 4,19,916/- रुपये के दावे के लिए पात्र पाया गया है और विभाग उक्त राशि का भुगतान करने के लिए तैयार था। हालाँकि, शेष सीसीएस दावे आदि और उस पर ब्याज के संबंध में, पत्र इस प्रकार है:

> "चूंकि 1,31,953/- रुपये का शेष दावा आवश्यक दस्तावेजों द्वारा समर्थित नहीं था, इस कार्यालय पत्र दिनांक 26.3.2008 के माध्यम से आपको दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने की सलाह दी गई थी, जिसमें दिखाया गया था कि परियोजना को द्विपक्षीय या बहुपक्षीय बाहरी सहायता द्वारा वित्त पोषित किया गया था। इसके विरुद्ध पत्र, आपने अपने पत्र दिनांक 31.3.2008 के माध्यम से उत्तर दिया था कि

परियोजना को ओईसीएफ फंड द्वारा वित्त पोषित किया गया था। अपने तर्क के समर्थन में आपने ओईसीएफ की वेबसाइट से कुछ जानकारी उद्धृत की है और दावा किया है कि परियोजना को ओईसीएफ द्वारा वित्त पोषित किया गया था, लेकिन कोई दस्तावेजी सबूत नहीं है आपने अपने दावे के समर्थन में प्रोजेक्ट अथॉरिटी यानी आरसीएफ लिमिटेड (राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड) से एक प्रोजेक्ट अथॉरिटी सर्टिफिकेट दिनांक 18.3.1983 प्रस्तुत किया है, जो आरसीएफ लिमिटेड द्वारा जारी किया गया है। माननीय बॉम्बे उच्च न्यायालय के समक्ष दायर संख्या 1174/03, जिसे पृष्ठ संख्या 31 पर याचिका में प्रदर्श-डी के रूप में संलग्न किया गया था, जिसमें दिखाया गया था कि परियोजना भारत सरकार के फंड द्वारा वित्त पोषित थी।

आप 7.4.2008 को व्यक्तिगत सुनवाई के लिए भी उपस्थित हुए थे और तर्क दिया था कि डीईईसी भाग II का भाग 'एफ' परियोजना प्राधिकरण यानी आरसीएफ लिमिटेड द्वारा प्रमाणित किया गया था, इसलिए, यह माना जाता है कि आपूर्ति ओईसीएफ फंड द्वारा वित्त पोषित की गई थी और देने का अनुरोध किया गया था इस राशि के लिए भी

आपका यह तर्क मान्य नहीं हो सकता क्योंकि डीईईसी भाग II के भाग 'एफ' में केवल चालान संख्या की जानकारी है। और तारीख, आपूर्ति की गई वस्तुओं का विवरण, मात्रा और उसका मूल्य। लेकिन इसका परियोजना के वित्त स्रोत से कोई लेना-देना नहीं है। वास्तव में, आपूर्ति का वित्तपोषण सरकार द्वारा किया गया था। भारत का कोष; इसलिए, यह आपूर्ति हैंड बुक ऑफ प्रोसीजर के पैरा 131 के अंतर्गत नहीं आती है, इस प्रकार, रुपये की सीमा तक सीसीएस लाभ के लिए पात्र नहीं है। 1,31,953/- रुपये के अतिरिक्त दावे के संबंध में आपके पत्र दिनांक 31.3.08 द्वारा 14,478/- की राशि जुटाई गई, आपको सूचित किया जाता है कि यह दावा मूल रूप से माननीय बॉम्बे उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका संख्या:1174/03 फ़ील्ड में शामिल नहीं किया गया था। जो भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष दायर एसएलपी संख्या 16917/2003 का विषय है। यहां तक कि यह दावा आवश्यक दस्तावेजों द्वारा समर्थित नहीं है, इसलिए, सीसीएस के आपके अतिरिक्त दावे पर विचार नहीं किया जा सकता है।

ब्याज के भुगतान के संबंध में, यह सूचित किया जाता है

कि डिबारिंग आदेश लागू था और अपीलीय प्राधिकारी द्वारा उनके आदेश दिनांक 18.6.1992 द्वारा कायम रखा गया था। यह 27.2.2008 तक यानी एसएलपी संख्या 16917/2003 के संबंध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की तारीख तक लागू था। विभाग की ओर से कोई देरी नहीं हुई। इस प्रकार, उपरोक्त दावे के विरुद्ध कोई ब्याज नहीं दिया जा सकता है।"

19. पूर्वोक्त निकाले गए संचार से यह स्पष्ट है कि सीसीएस के लिए पर्याप्त दावे की अनुमति दी गई है और रु. 1,31,953/- के शेष दावे को यह दिखाने के लिए दस्तावेजी साक्ष्य के अभाव में अस्वीकार कर दिया गया है कि परियोजना को द्विपक्षीय या बाहरी सहायता। द्वारा वित्त पोषित किया गया था। यह ध्यान रखना उचित है कि उक्त पत्र में इस बात का कोई संकेत नहीं है कि पहली बार में अपीलकर्ता को 4,19,916/- रुपये का सीसीएस दावा क्यों अस्वीकार कर दिया गया था।

20. श्री कुलकर्णी द्वारा प्रस्तुत किया गया था कि आये हैं निष्कर्ष यह है कि मामले के तथ्यों पर, ज़ब्ती का आदेश दिनांक 4 दिसंबर, 1985 को उच्च न्यायालय द्वारा वारंट नहीं किया गया था परिणामी राहत न देकर गलती की। सीसीएस के लिए दावा, क्योंकि इसे केवल ज़ब्ती आदेश के आधार पर अस्वीकार कर दिया गया था, जिसमें अपीलकर्ता को

डिफॉल्टर घोषित किया गया था। यह भी तर्क दिया गया कि, किसी भी मामले में, उत्तरदाताओं द्वारा अन्य स्वतंत्र निर्यात आदेशों के संबंध में सीसीएस को रोकने का कोई औचित्य नहीं था, जब उसमें निर्दिष्ट सभी शर्तें पूरी हो गई थीं। हम सुनवाई के समापन के बाद दायर लिखित दलीलों पर भी गौर कर सकते हैं। यह कहा गया है कि आरसीएफ ने अब 27 मई, 2008 को एक प्रमाण पत्र जारी किया है, जिसमें दिखाया गया है कि दो ऑर्डर, अर्थात् केसी 263 और केटी 995 को ओवरसीज इकोनॉमिक कॉरपोरेशन फंड (संक्षेप में 'ओईसीएफ') द्वारा वित्तपोषित किया गया था और इस प्रकार, इन दोनों के खिलाफ सीसीएस आदेश देय हैं. इस प्रकार, यह जनरल इंस्ट्रूमेंट्स कंपनी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया और ओआरएस था। अनुरोध किया कि उत्तरदाताओं को विलंबित भुगतान के लिए ब्याज सहित सीसीएस दावा तुरंत जारी करने का निर्देश दिया जाना चाहिए।

21. विदेश व्यापार महानिदेशक की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री गौरव अग्रवाल ने सीसीएस के अनुदान और उस पर ब्याज का विरोध करते हुए लिखित दलीलें दायर की। यह बताया गया है कि उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार, लाइसेंस को विशेष अग्रदाय लाइसेंस से परियोजना आयात लाइसेंस में परिवर्तित करने के बाद, अपीलकर्ता अब यह दावा नहीं कर सकता है कि आरसीएफ-थल परियोजना एक विदेशी वित्त पोषित परियोजना है, वे सीसीएस के लिए दावे का हकदार है। इस दलील के

समर्थन में कि सीसीएस केवल विशेष अग्रदाय लाइसेंस के मामले में ही स्वीकार्य है, हमारा ध्यान 30 मई, 1983 के विशेष अग्रदाय लाइसेंस में शर्त संख्या 4 की ओर आकर्षित किया गया था। जहां तक ब्याज के दावे का संबंध है, यह आग्रह किया जाता है कि इस तथ्य के अलावा कि ऐसा दावा पहली बार अप्रैल, 2003 में किया गया था, जब डब्ल्यू.पी. क्रमांक 1174/2003 दायर किया गया था, ज़ब्ती के आदेश को दुर्भावनापूर्ण नहीं कहा जा सकता क्योंकि, 30 अक्टूबर, 1985 को, यानी ज़ब्ती आदेश से पहले अपीलकर्ता को मंत्रालय से संपर्क करके अपने आयात को नियमित कराने की सलाह दी गई थी। दंडात्मक ब्याज के साथ सीमा शुल्क का भुगतान करके वित्त, लेकिन अपीलकर्ता ने उत्तरदाताओं की सलाह पर ध्यान नहीं दिया।

22. यह सामान्य बात है कि किसी भी व्यक्ति को तकनीकी प्रक्रिया द्वारा अनियमितताओं का शिकार नहीं होना चाहिए। नियम या प्रक्रियाएँ न्याय की दासियाँ हैं न कि न्याय की रखैल। हमें उसके साथ न्याय करना चाहिए। (ए.आर. अंतुले बनाम आर.एस. नायक1 देखें)। हालाँकि, वर्तमान मामले में, भले ही हमें लगता है कि अपीलकर्ता को जारी किए जाने वाले लाइसेंस की प्रकृति में भ्रम के कारण नुकसान हुआ है, लेकिन अपीलकर्ता की मुख्य प्रार्थना है कि विशेष अग्रदाय लाइसेंस को परियोजना आयात लाइसेंस में परिवर्तित किया जाए। उच्च न्यायालय, गलती का काफी हद

तक निवारण हो गया है।

23. उच्च न्यायालय के निर्देश (बी) के संदर्भ में, विशेष रूप से परियोजना आयात लाइसेंस में विशेष अग्रदाय लाइसेंस के रूपांतरण के बाद की उपरोक्त उल्लिखित घटनाओं के आलोक में मामले पर विचार करने के बाद, हमारी राय है कि इसमें - जहां तक सीसीएस दावे का सवाल है, अपीलकर्ता को कोई और राहत नहीं दी जा सकती। मामले को ध्यान में रखते हुए, प्रमाण पत्र, जिसे अब अपीलकर्ता को आरसीएफ द्वारा जारी किया गया बताया गया है, और 3 जून, 2008 की लिखित दलीलों के साथ संलग्न किया गया है, अपीलकर्ता के लिए कोई लाभ का नहीं है। फिर भी, हमारे निर्णय में, तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि दूसरे अपीलीय प्राधिकारी ने 4 दिसंबर, 1985 के ज़ब्ती के आदेश के आधार पर पारित 4 मई, 1987 के आदेश के अनुसार, केवल 31 मार्च, 1989 तक रोक की अवधि कम कर दी थी और तथ्य यह है कि उच्च न्यायालय ने अपने आदेश के तहत 7 अप्रैल, 2006 के आदेश में कहा गया है कि अपीलकर्ता के खिलाफ ज़ब्ती का आदेश अनावश्यक था, सीसीएस सी को जारी न करने के लिए विदेश व्यापार महानिदेशक के पास कोई उचित कारण नहीं था। उच्च न्यायालय द्वारा आदेश पारित करने पर कम से कम राशि। यह इस अपील की सुनवाई के दौरान ही पता चला उक्त उत्तरदाताओं के वकील ने दावे को पुनः प्राप्त करने की पेशकश की- संशोधन किया गया और इस

प्रकार अब आदेश दिनांक 8 अप्रैल, 2008 द्वारा अपीलार्थी का दावा 4,19,916/- रूपये का पाया गया है क्रम में होना. परिसर में, यह स्पष्ट है कि उत्तरदाता अपीलकर्ता को देय राशि को सीसीएस के रूप में बिना अधिकार के बरकरार रखा- कानून की संपूर्णता और इसके प्रति उत्तरदायी हैं उसे तुरंत भुगतान करें.

24. उपरोक्त चर्चा के मद्देनजर, अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है; उत्तरदाताओं को निर्देशित किया जाता है कि वे अपीलकर्ता को देय सीसीएस दावा आज से चार सप्ताह के भीतर 7 अप्रैल, 2006 से वास्तविक भुगतान की तारीख तक 9% प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ जारी करें।

25. हम स्पष्ट कर सकते हैं कि हमने रुपये के सीसीएस के लिए अपीलकर्ता के दावे की योग्यता पर कोई राय व्यक्त नहीं की है। निर्यात आदेश केटी-995 के विरुद्ध 14,478/- और साथ ही कच्चे माल के आयात पर अपीलकर्ता द्वारा देय सीमा शुल्क की दर, क्योंकि दोनों मुद्दों पर अपील जी संबंधित अपीलीय मंचों के समक्ष लंबित बताई गई है। जब भी अपीलें सुनवाई के लिए आएंगी, तो इन पर उपरोक्त किसी भी टिप्पणी से प्रभावित हुए बिना उनकी अपनी योग्यता के आधार पर सख्ती से निर्णय लिया जाएगा।

26. अपीलकर्ता इस अपील की लागत का हकदार होगा

एन.जे. अपील आंशिक रूप से स्वीकार की गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी मधुसूदन शर्मा (आर.एच.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरणः यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।

धन्यवाद।